9 OCT 11 2026.qxd 08-10-2026 22:50 Page 1

प्रकृति की देन भरोसे का नाम हिमालयन रॉक सॉल्ट

प्रयागराज - सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट लंबे समय से भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है और आयुर्वेद में इसके प्राकृतिक गुणों के कारण इसे विशेष स्थान दिया गया है। हाल के दिनों में, जैसे-जैसे लोग अपने खान-पान को लेकर जागरूक हो रहे हैं, रोजमर्रा के खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। यह प्राकृतिक और कम प्रोसेस की गई चीजों के प्रति लोगों के बढ़ते झुकाव को दर्शाता है, जो एक संतुलित और स्वस्थ जीवनशैली के अनुकूल हैं। आज बाजार में ढेरों विकल्प मौजूद हैं, ऐसे में किसी भरोसेमंद ब्रांड का चुनाव करना बहुत जरूरी हो जाता है। टाटा सॉल्ट हिमालयन रॉक सॉल्ट, भारत का नंबर 1 सेंधा नमक है जो लोगों की इस पसंद को टाटा ब्रांड के विश्वास और गुणवत्ता के भरोसे के साथ जोड़ता है। इसमें पोटैशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे प्राकृतिक मिनरल्स की थोड़ी मात्रा होती है, जो इसे इसकी खास पहचान देते हैं। सेंधा नमक में मौजूद मिनरल्स के कारण इसका रंग प्राकृतिक रूप से अलग-अलग होता है। जब इसे पानी में घोला जाता है और फिल्टर से छाना जाता है, तो नमक घुलकर एक साफ घोल बना लेता है, जबकि न घुलने वाले रंगीन कण यानी प्राकृतिक मिनरल्स फिल्टर पर ही रह जाते हैं। टाटा सॉल्ट हिमालयन रॉक सॉल्ट की हालिया लैब जांच से यह पुष्टि हुई है कि यह गुणवत्ता और सुरक्षा के सभी मानकों पर पूरी तरह खरा उतरता है।

अमेजनका ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शुरू

अमेज़न ने आज घोषणा की कि अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2026 सभी ग्राहकों के लिए शुरू हो रहा है, जो लाखों उत्पादों पर साल की सबसे कम कीमतें, प्राइम मेंबर्स के लिए अतिरिक्त बचत और कंपनी की अब तक की सबसे तेज़ फेस्टिव डिलीवरी लेकर आया है। ग्राहक स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ब्यूटी, होम, किचन और रोजमर्रा के जरूरी सामानों की खरीदारी टॉप ब्रांड्स और लाखों विक्रेताओं से कर सकते हैं। इन शानदार डील्स को बैंक ऑफर्स, नो-कॉस्ट ईएमआई, अमेज़न पे लेटर और एक्सचेंज ऑफर्स के जरिए और भी किफायती बनाया गया है और यह सब अमेज़न की अब तक की सबसे तेज़ स्पीड पर डिलीवर किया जाएगा। 8 अक्टूबर को एक सरप्राइज डिलाइटर के तहत, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद के चुनिंदा ग्राहक अमेज़न नाउ पर मिनटों में डिलीवर होने वाले आईफोन 16 को साल की सबसे कम कीमत पर पा सकते हैं। अमेज़न इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सौरभ श्रीवास्तव ने कहा, यह हमारे द्वारा ग्राहकों के लिए लाया गया अब तक का सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे फायदेमंद अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल है।

एप के जरिये आनलाइन कनेक्ट होगी प्रदेशकी हर महिला

लखनऊ (आससे.)। प्रदेश की महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में योगी सरकार तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था तैयार कर रही है। इसके तहत महिला सुरक्षा के लिए एक विशेष मॉनिटरिंग सेल तैयार किया जा रहा है, जिसमें एप के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं के लिए शिकायत दर्ज कराने और उस पर एक्शन लेने की प्रक्रिया को और सुगम बनाने की तैयारी है। प्रस्तावित व्यवस्था में क्यूआर कोड स्कैन करते ही महिला अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगी। वहीं एप के माध्यम से महिलाओं को ऑनलाइन सुरक्षा तंत्र से जोड़ने की व्यवस्था भी की जाएगी।इस पहल की खास बात यह होगी कि महिला सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों और उनसे संबंधित कार्रवाई की निगरानी के लिए व्यवस्था को प्रदेश स्तर पर जोड़ा जाएगा। लखनऊ स्थित कमांड सेंटर से सभी 75 जिलों पर नजर रखने की योजना है। कमांड सेंटर में तैनात विशेष सेल महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग के साथ ही जरूरत के अनुसार विभिन्न विभागों और संबंधित तंत्र के बीच समन्वय की भूमिका निभाएगा। इससे

क्यूआर स्कैन करते ही कर सकेंगी शिकायत

शिकायतों को संबंधित स्तर तक पहुंचाने और उनके निस्तारण की निगरानी को अधिक व्यवस्थित बनाने का प्रयास होगा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबिता सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल के विस्तार के उपरांत गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से महिला आयोग के आगामी कार्यों, दायित्वों और प्राथमिकताओं के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। डॉ. बबिता सिंह चौहान ने आयोग द्वारा महिलाओं के हित में किए जा रहे कार्यों और आगामी कार्ययोजना की जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी। प्रस्तावित व्यवस्था में महिलाओं को शिकायत के लिए अलग-अलग माध्यमों की तलाश करने की जरूरत कम होगी। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद महिला शिकायत दर्ज कर सकेगी। इसके साथ ही एप के जरिए ऑनलाइन कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की तैयारी है। यानी तकनीक को महिला सुरक्षा के तंत्र से सीधे जोड़कर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने पर जोर है।

सीजेपीके प्रदर्शनको लेकर पुलिस अलर्ट

नयी दिल्ली (आससे)। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मतदाता सूची में एसआईआर की प्रक्रिया के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके बावजूद सीजेपी के प्रदर्शन की घोषणा को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की डीसीपी सृष्टि पांडे ने कहा कि प्रदर्शन के मद्देनजर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और सुरक्षा के सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने लोगों से गैरकानूनी प्रदर्शन में शामिल न होने की अपील की है। डीसीपी ने कहा कि धारा 163 लागू होने के कारण किसी भी तरह का जमावड़ा गैरकानूनी माना जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

10वीं की छात्राने जहरीला पदार्थ खाकर दी जान

हापुड़ (एजेंसी)। यूपी के हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव स्थित एक स्कूल में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने कक्षा दसवीं की छात्रा से छेड़छाड़ कर दी। इससे क्षुब्ध छात्रा ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर छात्रा को गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां मंगलवार की रात उपचार के दौरान छात्रा की मौत हो गयी। अब पुलिस ने पिता की तहरीर पर अज्ञात युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। गांव निवासी एक व्यक्ति ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनकी पुत्री गांव स्थित एक स्कूल में कक्षा दसवीं की छात्रा थी। पिछले कई दिनों से उसकी कक्षा के की कुछ लड़के उनकी पुत्री को परेशान कर रहे थे। इतना ही नहीं आरोपी उनकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ भी कर रहे थे। मंगलवार की शाम करीब साढ़े पांच बजे उनके गांव के ही एक युवक ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी उनके पुत्र को दी। घर पर पता चलने के बाद उनकी पुत्री काफी परेशान हो गई।

अखिलेशने अयोध्यासे चुनाव लड़नेकी मुख्यमंत्रीको दी चुनौती

लखनऊ (आससे)। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दी। अखिलेश ने कहा कि भाजपा लगातार सर्वे करा रही है, लेकिन हर सर्वे में पीछे छूट रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को अयोध्या में कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतने ही आश्वस्त हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं। अखिलेश यादव पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय के पैतृक गांव कृष्णापुर खानपुर रसूलाबाद में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में शामिल होने पहुंचे थे। हालांकि, कार्यक्रम स्थल से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन नहीं किए। इसे लेकर भाजपा ने उन पर निशाना साधा। भागवत कथा में



अयोध्या में भाजपा को नहीं मिल रहा प्रत्याशी

अखिलेश यादव ने भगवान कृष्ण के जीवन और उनके संदेश का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कृष्ण का जीवन सामाजिक न्याय, प्रेम, दया, अपनापन और बंधुत्व का संदेश देता है। ईश्वर और न्याय के दरबार में ऊंच-नीच का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कृष्ण-सुदामा की मित्रता और अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण की भूमिका का उदाहरण देते हुए कहा कि वंचित लोगों को सम्मान देना ही सामाजिक न्याय है। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अयोध्या के विकास को और गति दी जाएगी। जमीन और मकान अधिग्रहण के मामलों में लोगों को उचित मुआवजा और बाजार भाव दिलाने का प्रयास होगा। उन्होंने महिलाओं को भविष्य में हर साल 40 हजार रुपये देने की बात भी कही। अखिलेश ने कहा कि इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद पवन पांडेय तारीख तय करें और पूरा समाजवादी पार्टी परिवार अयोध्या जाकर रामलला का आशीर्वाद लेगा।

पृष्ठ एक का शेष

ज्ञानेशके...

भारी सुरक्षा बल तैनात किया। केंद्रीय दिल्ली में पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाई गई। मालूम हो कि विपक्ष ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का समय भी मांगा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक, विपक्षी नेताओं ने 2 अक्टूबर को पहली चिट्ठी भेजी थी और 5 अक्टूबर को नेताओं के नामों के साथ दोबारा अनुरोध किया। बता दें कि इससे पहले 6 और 7 अक्टूबर को भी दिल्ली में विपक्षी सांसदों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी थी। 6 अक्टूबर को सांसदों ने चुनाव आयोग की ओर मार्च किया था, जबकि 7 अक्टूबर को जंतर-मंतर जाने की कोशिश के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था। 6 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर कुछ नेताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर मतदाता सूची को अद्यतन और शुद्ध करने की प्रक्रिया है, जबकि भाजपा और आयोग विपक्ष के आरोपों को खारिज करते रहे हैं।

आपराधिक...

मार्च से पहले राहुल गांधी ने कहा कि करीब 300 सांसद शांतिपूर्ण धरना देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के पहले दिन उन्हें निर्वाचन आयोग के कार्यालय के पास रोक दिया गया, जबकि दूसरे दिन जंतर-मंतर जाने से रोका गया और हमारे लोगों को मारा गया। राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत और ज्ञानेश कुमार ने आपराधिक साजिश करके देश को हाईजैक किया है। संविधान को नष्ट किया और वोट चोरी की है। उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जायेगा। यह हमारी गारंटी है और आप ऐसा होते हुए देखेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी सांसद गांधी स्मारक जा रहे हैं, जहां वह धरना देंगे और शांतिपूर्वक प्रार्थना करेंगे कि मोदी और शाह को सद्बुद्धि मिले। खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोगों से वोट देने का अधिकार छीन रही है। मोदी और शाह उस आजादी को छीन रहे हैं, जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे महान नेताओं ने देश को दिलाई थी।

जीएसटी...

इस सीमा से कम के सभी लंबित नोटिस भी वापस ले लिए जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि ऐसे नोटिस पहले जारी किए गए थे, तो उन्हें भी वापस लिया जाएगा। यह निर्णय करदाताओं पर छोटे मामलों का बोझ कम करने के लिए लिया गया है। इससे जीएसटी प्रणाली में और अधिक स्पष्टता आएगी। यह कदम प्रक्रियाओं को सरल बनाने में सहायक होगा।

सपा सरकार...

अवधारणा से जोड़ा। राजनीतिक बयान देते हुए अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। उन्होंने अयोध्या विधानसभा से पवन पांडेय को प्रत्याशी बनाया है और मैदान खुला पड़ा है। सपा की सरकार बनने पर अयोध्या को वैश्विक स्तर पर विकसित किया जाएगा। अखिलेश ने अयोध्या को पर्यटन स्थल के बजाय तीर्थ स्थल बताया और विकास की बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये दिए जाएंगे।

डाक्टरोंको...

ब्रांडेड दवाएं या तर्कहीन दवा संयोजन लिखने के लिए प्रभावित करती हैं। केंद्र ने अदालत को बताया कि यूसीपीएमपी-2024 फिलहाल लागू है और डॉक्टरों के अनैतिक आचरण पर पहले से कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। हालांकि, फार्मास्युटिकल कंपनियों के आचरण को सीधे नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट वैधानिक व्यवस्था की कमी है। इसी नियामकीय खामी की जांच अब विशेषज्ञ समिति करेगी। सरकार के अनुसार, यूसीपीएमपी के तहत अब तक तीन शिकायतें मिली हैं। इनमें एक मामले में करीब 30 डॉक्टरों को महंगी यात्राएं कराने के आरोप पर संबंधित कंपनी को फटकार लगाई गई और डॉक्टरों की सूची कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को भेजी गई।

आलोचना...

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर दोष मढ़ा जाता है, जबकि उन्हीं मशीनों से मिली जीत पर कोई सवाल नहीं उठाता। दशकों तक राज करने वाले दल अब उस पूरी चुनावी व्यवस्था को धांधली वाला बता रहे हैं, जिसने उन्हें सत्ता दी थी। पूर्व जजों ने समझाया कि भारत का चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 से अपनी शक्ति लेता है। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर मतदाता सूची को कार्यपालिका की पहुंच से दूर एक स्वतंत्र आयोग को सौंपा था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है, जो पहले आम चुनाव के समय से ही नियमित रूप से होती आई है। इसका उद्देश्य मृत लोगों के नाम हटाना, दोहरी प्रविष्टियां खत्म करना और छूटे हुए पात्र नागरिकों को जोड़ना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रक्रिया को पूरी तरह वैध और निष्पक्ष माना है, फिर भी तथ्यों को दरकिनार कर भ्रम फैलाया जा रहा है। पूर्व जजों ने साफ चेतावनी दी है कि जनता का विश्वास ही लोकतंत्र की असली ताकत है। अगर नागरिकों को लगातार यह समझाया जाएगा कि उनके वोट का कोई मोल नहीं है, तो वे मतदान व्यवस्था पर भरोसा करना छोड़ देंगे। जब मतपेटी अपनी अहमियत खो देती है, तब सड़कों पर अराजकता शुरू हो जाती है। कुछ अराजक और सीमांत तत्व इस खाली जगह का फायदा उठाते हैं, जिनमें से कुछ देश के भीतर से और कुछ सीमाओं के पार से निर्देश लेते हैं। संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेदारी साझी है। सांविधानिक संस्थाएं जनता के भरोसे और पूर्ण पारदर्शिता से अपनी साख बनाती हैं। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे अपनी शिकायतें कानूनी प्रक्रिया और साक्ष्यों के आधार पर ही उठाएं। वहीं मीडिया को भी कल्पना और सत्यापित तथ्यों के बीच का अंतर जनता तक स्पष्ट रूप से पहुंचाना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में जनता का विश्वास ही शासन की वास्तविक रीढ़ होता है। सांविधानिक संस्थाएं किसी सरकार की निजी संपत्ति नहीं हैं, बल्कि वे भारत के 140 करोड़ नागरिकों की हैं। इनकी विश्वसनीयता पर हमला सीधे तौर पर उन संस्थाओं पर हमला है जो नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करती हैं। अंत में सभी 42 पूर्व जजों ने देश के हर नागरिक से संविधान और इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के बचाव में मजबूती से खड़े होने का आह्वान किया है।

एनडीए...

से ज्यादा के चयन की प्रक्रिया चल रही है। ओलम्पिक, राष्ट्रमंडल या एशियाई खेलों में जिन्होंने पदक जीता है, हमने उन्हें सीधी भर्ती से यूपी पुलिस में डिप्टी एसपी का पद दिया है। ऐसे सात खिलाड़ियों को हम नौकरी दे चुके हैं। 2017 से पहले यह संभव नहीं था। सीएम ने आगे कहा कि यूपी के अंदर एक समय था जब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही जिंदगी होती थी। इससे पहले और बाद में घर से नहीं निकल सकते थे। 64 हजार हेक्टेयर लैंड को हम लोगों ने माफिया के कब्जे से खाली कराई। हम खेल ग्राउंड, मिनी स्टेडियम और हर मंडल में एक स्पोर्ट्स कॉलेज देने जा रहे हैं। आज यूपी में अपनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होने जा रही है। हम प्रधानमंत्री की उस बात से सहमत हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमारा कोई ब्रांड एंबेसडर बन सकता है तो खिलाड़ी बन सकता है। जो खेलेगा वो खिलेगा। सीएम ने डीजीपी से कहा कि इन सब खिलाड़ियों को एक-एक गांव गोद दे दीजिए। वहां पर ये लोग खेलकूद के कार्यक्रम कराएं। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस को कभी छोड़ना मत। आपकी असली प्रतिभा पसीने में है। यह अभी शुरुआत है। आगे प्रमोशन के बहुत विकल्प हैं। उन्होंने युवाओं को नसीहत दी कि ज्यादातर युवा रील में व्यस्त हैं। रील में लाइक मिलते हैं, लेकिन खेल में लाइफ मिलती है। चुनना आपको है। उन्होंने पीडीए को निशाने पर लिया। कहा कि पहले प्रदेश डुबाओ अलायंस था। वही लोग नौकरियों में डाका डालते थे। उनके राज में सैफई और सिफारिश था। आज एनडीए की सरकार है, यानी नौकरी देंगे अलायंस की सरकार है। अब हमने ऐसी व्यवस्था बना दी है, कि कोई आपकी नौकरी, आपके प्रमोशन को टाल नहीं सकता। यदि किसी ने कोशिश भी की तो फिर हम उसे टाल देंगे। सीएम ने कहा कि पहले की सरकार ने 10 लाख गुंडे खड़े किए थे। हमने 10 लाख युवाओं को नौकरी दी है। पहले हर दिन हत्या जैसी खबरें आती थीं। रिवर फ्रंट घोटाले की खबर आती थी। लेकिन, आज खबर आती है कि मेरठ में खुलेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। जब सपा युवाओं की नियुक्तियों की बात करती है तो लगता है पानी में तैरने वाला मगरमच्छ शांति का संदेश दे रहा हो। ऐसे शांति का संदेश देने वाले मगरमच्छों से सावधान रहिए। इससे पहले सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि मैदान में मेधा, उपलब्धि पर सम्मान और प्रतिभा को राष्ट्र सेवा का अवसर देना ही 'नए उत्तर प्रदेश' की नई खेल संस्कृति है। इसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए पुलिस विभाग में कुशल खिलाड़ी कोटे के तहत चयनित 470 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिये गये। सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए खुल रहे सरकारी सेवा के ये द्वार उस बदलाव की तस्वीर हैं, जो प्रदेश ने वर्ष 2017 के बाद देखा है। उनके मुताबिक इससे पहले खेल कोटा उपेक्षित था और भर्तियों में प्रतिभा से अधिक सिफारिश और पहुंच की चर्चा होती थी। सीएम ने दावा किया कि डबल इंजन सरकार ने खेल प्रतिभाओं को रोजगार और सुरक्षित भविष्य से जोड़ने का काम किया है।

संक्षिप्त

फारस की खाड़ी और काला सागर में संघर्ष के दौरान 16 भारतीय नाविकों की जान गयी -सरकार

नयी दिल्ली। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव विजय कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष में 16 भारतीय नाविकों की जान गई है। कुमार ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत सरकार हॉर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्र से 4,232 भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस ला चुकी है।उन्होंने कहा कि 28 फरवरी को अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से हॉर्मुज जलडमरूमध्य और फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों में जहाजों पर मिसाइल हमले लगातार बढ़े हैं। कुमार ने कहा कि उस दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, जिसमें देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई और कई शीर्ष कमांडर मारे गए। पश्चिम एशिया में स्थित हॉर्मुज जलडमरूमध्य एक संकरा समुद्री मार्ग है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 28 फरवरी से काला सागर में जारी संघर्ष में पांच भारतीय नाविकों की जान जा चुकी है।

चित्रकूट में बनेगा बचपन डे केयर सेंटर, सरकार ने जारी की पहली किश्त

लखनऊ (आससे.)। दिव्यांगजनों के कल्याण, विकास और सुगम पुनर्वास की दिशा में योगी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने चित्रकूट जनपद में बचपन डे केयर सेंटर के भवन निर्माण के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।5 करोड़ 62 लाख 82 हजार रुपये निर्धारित की गई है, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्माण कार्य शुरू करने के लिए 3 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त अवमुक्त कर दी गई है।योगी सरकार लगातार दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। चित्रकूट में बचपन डे केयर सेंटर की स्थापना इसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इससे दिव्यांग बच्चों के कल्याण, विकास, देखभाल और सुगम पुनर्वास के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं विकसित होने की उम्मीद है। मूल्यांकन समिति की संस्तुति के आधार पर सेंटर के भवन निर्माण की कुल परियोजना लागत 562.82 लाख रुपये (5.62 करोड़ रुपये से अधिक) निर्धारित की गई है। शासन की ओर से जारी स्वीकृति के अनुसार निर्माण कार्य सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही प्रारंभ किया जाएगा। निर्माण के दौरान निर्धारित गुणवत्ता, मानकों और विशिष्टियों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग और कार्यदायी संस्था की होगी।

सरकार ने निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सभी आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां और पर्यावरणीय क्लियरेंस प्राप्त करना भी अनिवार्य किया है। इससे परियोजना को निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप पूरा करने में मदद मिलेगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव राकेश कुमार यादव ने निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश को आधिकारिक स्वीकृति पत्र जारी कर दिया है।

बिहारके मजदूरोंके साथ धोखा : लखनऊ में झांसा देकर एमपी भेजा, जबरन बनाया गया बंधक

लखनऊ (आससे)। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रोजगार दिलाने का झांसा देकर बिहार के गोपालगंज जिले के करीब एक दर्जन मजदूरों को मध्य प्रदेश के रतलाम में बंधक बनाकर काम कराने का गंभीर मामला सामने आया है। रतलाम जिले के जावड़ा गांव स्थित दुर्गम पहाड़ी इलाके में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर फंसे मजदूरों ने वीडियो संदेश जारी कर अपनी सुरक्षा की गुहार लगायी है। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उनसे जबरन सरिया बांधने समेत अन्य भारी काम कराया जा रहा है, लेकिन मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा। उनका कहना है कि जब भी वे घर लौटने या काम का विरोध करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। पीड़ित मजदूरों ने पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ नेता मिथिलेश तिवारी और स्थानीय प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की अपील की है। फंसे मजदूरों में बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिघवा-दुबौली गांव निवासी साजन मांझी, सतेंद्र महतो, मनोज राय, अरुण महतो, रामाशीष मांझी, संतोष प्रसाद, विकास मांझी और ललन मांझी शामिल हैं। इसके अलावा डोमाहाता गांव के कमल कुमार और छोटू कुमार भी शामिल हैं। मजदूरों के अनुसार, डोमाहाता गांव के ही एजेंट धर्मेंद्र यादव ने उन्हें लखनऊ में अच्छा काम और बेहतर वेतन दिलाने का भरोसा देकर घर से बुलाया था। आरोप है कि बाद में उन्हें धोखे से रतलाम के जावड़ा स्थित कंस्ट्रक्शन साइट पर भेज दिया गया। मजदूरों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गोपालगंज में उनके परिजनों में दहशत का माहौल है। परिजन मजदूरों की सुरक्षित वापसी को लेकर चिंतित हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए नई दिल्ली स्थित बिहार भवन ने भी तत्काल काररवाई शुरू की है। बिहार भवन के संयुक्त श्रम आयुक्त कुमार दिग्विजय ने रतलाम के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर पुलिस बल के साथ तत्काल काररवाई करने को कहा है। बिहार भवन ने मांग की है कि 'बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976' और अन्य श्रम एवं दंड कानूनों के तहत मजदूरों को तत्काल मुक्त कराया जाय। रेस्क्यू के बाद उन्हें भोजन, सुरक्षित आश्रय और चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी जाय।

सपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन

वोट चोर गद्दी छोड़ो एवं लोकतंत्र बचाओ जैसे नारे लगाते रहे

लखनऊ (आससे.)। समाजवादी पार्टी ने गुरूवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। सपा महानगर अध्यक्ष फाकिर सिद्दीकी के नेतृत्व में छात्र सभा, महिला सभा और यूथ ब्रिगेड के सैकड़ों कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ता वोट चोर गद्दी छोड़ो व लोकतंत्र बचाओ जैसे नारे लगाते रहे। कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां और बैनर थे। प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल उठाये। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता बनाए रखना समय की सबसे बड़ी जरूरत है।

प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की मांग करते हुए कहा कि चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर जनता के बीच अविश्वास का माहौल बन रहा है, जिसे दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस दौरान लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री जितेन्द्र यादव जीतू ने अधिवक्ता के साथ ज्ञानेश कुमार के पुतले भी फूंका। जबकि महानगर महासचिव गौरव सिंह यादव ने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 सार्वजनिक रूप से सभी के समक्ष पढ़ के सुनाया।

कंगाल पाकिस्तान ने फिर फैलाये हाथ

आईएमएफ देगा 11,619 करोड़ का कर्ज

इस्लामाबाद (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान को करीब 1.2 अरब डॉलर की नई मदद देने पर शुरुआती सहमति दे दी है। इसमें करीब एक अरब डॉलर आईएमएफ के मुख्य कर्ज कार्यक्रम के तहत मिलेंगे। इसके अलावा 21 करोड़ डॉलर ऐसे कार्यक्रम के तहत मिलेंगे, जिसका मकसद पाकिस्तान को जलवायु और लंबे समय के दूसरे खतरों से निपटने में मदद करना है। हालांकि, पैसे मिलने के लिए आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड की मंजूरी अभी बाकी है।

आईएमएफ की टीम और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच लंबी बातचीत के बाद यह समझौता हुआ है। आईएमएफ की टीम का नेतृत्व इवा पेत्रोवा ने किया। यह समझौता पाकिस्तान के दो कार्यक्रमों की समीक्षा के बाद हुआ है। मंजूरी मिलने पर दोनों कार्यक्रमों के तहत पाकिस्तान को अब तक कुल करीब 5.7 अरब डॉलर मिल जाएंगे। आईएमएफ के मुताबिक, पाकिस्तान ने पश्चिम एशिया के संघर्ष के असर के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को संभाले रखा। आईएमएफ के मुताबिक, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार दिख रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआती तीन तिमाहियों में देश की आर्थिक वृद्धि 4 फीसदी रही। हालांकि, महंगी ऊर्जा और सामान की सप्लाई में दिक्कतों से रफ्तार कुछ कम हुई है। पूरे वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि 3.6 फीसदी रहने का अनुमान है। वहीं, मई में सबसे ज्यादा रहने के बाद सितंबर में महंगाई घटकर करीब 10.3 फीसदी हो गई। आईएमएफ के मुताबिक, विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों से मिलने वाले पैसे यानी प्रवासी धन की वजह से देश का चालू खाता लगभग संतुलित रहा। सितंबर के अंत तक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर करीब 21 अरब डॉलर हो गया। पाकिस्तान की संप्रभु रेटिंग में सुधार और अंतरराष्ट्रीय बाजार में दोबारा पहुंच को भी आईएमएफ ने सकारात्मक संकेत बताया है। आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान के सामने अभी भी कई बड़े खतरे हैं। इनमें भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव, दुनिया में कर्ज और पैसे की स्थिति का मुश्किल होना और व्यापार में रुकावट शामिल हैं। यानी आईएमएफ से मिलने वाली नई